करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

नवंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **5**

- उत्तर प्रदेश में ज़ीका वायरस रोग 5
- उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलिंडर 5
- बटेश्वर पशु मेला 5
- अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन 6
- पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 6
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 6
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड 7
- लीड्स रैंकिंग 2021 7
- उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 8

नोट :

- टोक्यो पैरालम्पिक-2020 के पदक विजेता तथा प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया 9
- केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 735 पेयजल योजनाओं को मंज़ूरी दी 9
- अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 10
- आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 10
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 10
- 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व-झाँसी जलसा' 11
- नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन 11
- रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क 12
- पीएम द्वारा प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण 12
- गंगा एक्सप्रेस-वे को मिली पर्यावरण मंज़ूरी 13
- यूपी के 35 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले: एडीआर रिपोर्ट 13
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि 14
- प्रधानमंत्री ने किया एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास 15

नोट :

- निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 15
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक : उत्तर प्रदेश तीसरा सर्वाधिक गरीब राज्य 16
- इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर चलेगा अभियोग 16
- अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश ने फतह किया माउंट पितालसु 17
- नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान 17

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में ज़ीका वायरस रोग

चर्चा में क्यों ?

- 31 अक्टूबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जीका वायरस का प्रसार रोकने के लिये एक उच्चस्तरीय मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग को डोर-टू-डोर सैनिटाइज़ेशन एवं फॉगिंग के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रदेश में ज़ीका वायरस रोग का पहला मामला 22 अक्टूबर, 2021 को आया था, जिसके पश्चात् राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहद् स्तर पर सैनिटाइज़ेशन, फॉगिंग एवं एंटीलार्वा केमिकल स्प्रे किया जा रहा है, ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जा सके।
- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है, ताकि वायरल बुखार सहित वाहक जनित बीमारियों से संबंधित लक्षणों वाले लोगों की पहचान की जा सके।
- उल्लेखनीय है कि ज़ीका वायरस रोग मुख्यरूप से एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। इसके अतिरिक्त ज़ीका वायरस गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण में, यौनसंपर्क, रक्त और उत्पादों के आधार तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी पैलता है।
- गर्भावस्था के दौरान ज़ीका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जन्म माइक्रोसिपैली और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है।
- ज़ीका के उपचार के लिये कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इससे निपटने के लिये शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बुखार तथा दर्द से निजात पाने हेतु रिहाइड्रेशन एवं एसिटामिनोपेन का प्रयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलिंडर

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलिंडर लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इसका निर्माण आई.ओ.सी.एल. द्वारा किया जा रहा है। इसे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर में घर-घर पहुँचाने की योजना है।
- यह ब्लो मोल्डेड इनर लाइनर से बनी तीन परतों वाला सिलिंडर है, जिसे पॉलीमर फाइबर ग्लास की मिश्रित परत से ढका जाता है।
- यह सिलिंडर हल्का एवं जंगरोधक होने के साथ आग लगने की स्थिति में ब्लास्ट नहीं होता है। इसके द्वारा सिलिंडरों से गैस चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी।

बटेश्वर पशु मेला

चर्चा में क्यों ?

- 2 नवंबर, 2021 से आगरा ज़िले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल 'बटेश्वर' में पशु मेले का शुभारंभ हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह भारत का एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो यमुना और शौरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिये जाना जाता है।
- यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एक बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है।
- यह मेला तीन चरणों मे पूरा होता है। पहले चरण में- ऊँट, घोड़े और गधों की बिक्री होती है, दूसरे चरण में- गाय आदि अन्य पशुओं की तथा अंतिम चरण में- सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं।

अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

- 3 नवंबर, 2021 को अयोध्या में सरयू तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में पाँचवे दीपोत्सव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से ही छोटी दीपावली के अवसर पर प्रतिवर्ष दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- इस बार आयोजित पाँचवे दीपोत्सव में 11 लाख 90 हज़ार दीप जलाए गए, जिनमें से 9 लाख 54 हज़ार जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।
- दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय और बीपीएल कार्ड-धारकों को होली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड-धारकों को प्रति माह 35 किग्रा. चावल और गेहूँ के साथ दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, नमक और चीनी प्रदान की जाएगी, जबकि बीपीएल कार्ड-धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा. चावल और गेहूँ के साथ दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और नमक दिया जाएगा।

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में बंगलुरू स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्कोर -1.418 अंकों के साथ सबसे कम रहा, जबकि केरल (1.618 अंक) को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस सूचकांक में पीएसी ने शासन के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभों- विकास, इक्विटी और स्थिरता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की है। शासन के तीन स्तंभों में से प्रत्येक को पाँच शासन अभ्यास विषयों (थीम) में विभाजित किया गया है।
- सूचकांक में राज्यों के लिये इक्विटी स्कोर पाँच विषयों पर आधारित थे- आवाज और जवाबदेही; सरकार की प्रभावशीलता; कानून का शासन; नियामक गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- वहीं स्थिरता मानकों का मूल्यांकन स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण प्रदूषण व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के आधार पर किया गया, जबकि विकास स्कोर के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय प्रदर्शन और बुनियादी ढाँचे और विकास पर सरकारी खर्च विषयों को शामिल किया गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

चर्चा में क्यों ?

- 5 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने आज़मगढ़ दौरे के दौरान बताया गया कि इसी माह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन 6-लेन एक्सप्रेस वे है, जो गाज़ीपुर शहर को राज्य की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा।
- इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- यह उत्तर प्रदेश के 9 ज़िलों- लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आज़मगढ़, मऊ और गाज़ीपुर से होकर गुज़रेगा। एक्सप्रेस-वे को वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आज़मगढ़ ज़िले में बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 7 नवंबर, 2021 को राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 2.75 लाख करोड़ रुपए का वितरण कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 27 विभागों की 137 योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में 2.75 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जैसे-
  - 2020 में अप्रत्याशित कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाखों किसानों, नरेगा श्रमिकों, अन्य राज्यों के मज़दूरों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और पेंशनभोगियों के खातों में सीधे पैसा भेजा गया।
  - उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 86 लाख छोटे सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज़ माफ किये और राशि को डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।
  - पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2.54 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में डीबीटी के ज़रिये 27,521 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं।
  - 6 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते और स्कूल बैग खरीदने के लिये 1100 रुपए ट्रांसफर किये गए। इस योजना से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को लाभ होगा।
- उल्लेखनीय है कि डीबीटी भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के तरीके के रूप में शुरू की गई एक पहल है।

लीड्स रैंकिंग 2021

चर्चा में क्यों ?

- 8 नवंबर, 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स), 2021 रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7 स्थान की छलांग लगाते हुए 13वें से 6वें स्थान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- गुजरात 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है।
- इस बार शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश छठे, ओडिशा सातवें, कर्नाटक आठवें, आंध्र प्रदेश नौवें और तेलंगाना 10वें स्थान पर हैं।

नोट :

- वहीं पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम क्रमश: 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें स्थान पर हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी केंद्रशासित क्षेत्रों की सूची में, जम्मू-कश्मीर सबसे ऊपर है। केंद्रशासित क्षेत्रों में दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है।
- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये ज़रूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है, जो देश के व्यापार में सुधार और लेनदेन लागत को कम करने के लिये ज़रूरी है।
- गौरतलब है कि पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण रैंकिंग जारी नहीं की गई थी। गुजरात 2018 और 2019 दोनों ही वर्ष रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर था।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 10 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना' के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
  - इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी' का गठन किया जाएगा तथा सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई जाएगी। इस काउंसिल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
  - योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि, यानि की शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था कार्य से संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों से की जाएगी।
  - 'उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी' का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतिकार्ड आयोडाइज्ड नमक 1 किग्रा., दाल/साबुत चना 1 किग्रा., खाद्य तेल 1 लीटर एवं खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण माह दिसंबर, 2021 से मार्च 2022 तक किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- मंत्रिपरिषद ने जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पी.टी.एस.) की क्षमता दोगुनी किये जाने हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को भी मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
- मत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिये ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के.जी.एम.यू.), लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
- मंत्रिपरिषद ने संकल्प पत्र 2017 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को 1.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकमुश्त दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा-13 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने की स्थिति में मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है।

नोट :

टोक्यो पैरालम्पिक-2020 के पदक विजेता तथा प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टोक्यो पैरालम्पिक गेम्स-2020 में भारत के पदक विजेता एवं प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मानित किया। उन्होंने खेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने टोक्यो पैरालम्पिक में 19 पदक जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को व प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों को कुल 32.50 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण किया।
- इस अवसर पर मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त से 5 सितंबर, 2021 तक टोक्यो पैरालम्पिक-2020 में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में प्रतिभाग कर 5 स्वर्ण, 8 रजत व 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते। इन खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के थे।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिये 6 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिये 4 करोड़ रुपए व कांस्य पदक के लिये 2 करोड़ रुपए प्रदान किये जा रहे हैं।
- इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश से बाहर के खिलाड़ियों के लिये स्वर्ण पदक के लिये 2 करोड़ रुपए, रजत पदक के लिये 1.50 करोड़ रुपए व कांस्य पदक के लिये 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, जिन्होंने टोक्यो पैरालम्पिक में प्रतिभाग किया, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के बावजूद पदक नहीं जीत पाए, राज्य सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को भी 25-25 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 735 पेयजल योजनाओं को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

- 12 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के विंध्य और बुंदेलखंड जैसे- जल-दबाव वाले क्षेत्रों में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिये 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- जल शक्ति मिशन के क्रियान्वयन की गति को तेज़ करने के लिये राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिये राज्य द्वारा प्रस्तुत 1,882 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
- इन योजनाओं से 33 ज़िलों के 1,262 गाँवों की करीब 39 लाख की आबादी को कवर किया जाएगा। समिति द्वारा 735 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंज़ूरी के तहत प्रदेश के 4.03 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये राज्य को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया।
- अब तक राज्य के 2.64 करोड़ में से 34 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है। 2021-22 में राज्य ने 78 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।
- राज्य सरकार अगले महीने से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना शुरू करेगी। इसके लिये कई इलाकों में ट्रायल किये जा रहे हैं।
- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिये की जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है।
- SLSSC, भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) के नॉमिनी के साथ जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिये एक राज्यस्तरीय समिति के रूप में कार्य करती है।

नोट :

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

- 13-14 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दोदिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन का उद्घाटन 13 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था।
- आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया।
- इस सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में राजभाषा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना है।
- इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की स्मारिका का भी विमोचन किया।

आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 13 नवंबर, 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2017 के घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया गया था। विगत 05 वर्षों में 10 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
- ये 10 विश्वविद्यालय हैं- माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ, युनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय 49.42 एकड़ में बनाया जा रहा है। प्रथम चरण की लागत 108.05 करोड़ रुपए है।
- इस परियोजना की अवधि 18 माह है और निर्माण कार्य जून, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय से आजमगढ़ व मऊ जनपद के 400 महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा, जिससे 2.66 लाख विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 16 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर ज़िले के करवल खीरी में 341 किमी. लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। इसके खुलने के बाद गाज़ीपुर से राजधानी दिल्ली का सफर 10 घंटों में हो सकेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। एक्सप्रेस-वे लखनऊ के चाँद सराय से शुरू होगा और गाज़ीपुर तक पहुँचेगा। यह एक्सप्रेस-वे 9 ज़िलों- लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आज़मगढ़, मऊ और गाज़ीपुर को जोड़ेगा।
- इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में 36 महीने का वक्त लगा तथा इसकी लागत 22 हज़ार 497 करोड़ रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में आज़मगढ़ में रखी थी।
- इस अवसर पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के आकस्मिक उपयोग के लिये इस एक्सप्रेस-वे पर बनी 3.2 किमी. लंबी हवाई पट्टी पर एयर शो किया गया, जिसमें राफेल, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो ऑपरेशन (यानी, विमान उड़ते हुए आते हैं और ज़मीन छूते ही दोबारा उड़ जाते हैं) के तहत करतब दिखाया तथा जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की।
- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 3 अन्य एक्सप्रेस-वे के तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें 300 किमी. लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा को जोड़ेगा। 90 किमी. लंबा गोरखपुर एक्सप्रेस-वे गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आज़मगढ़ को जोड़ेगा तथा 600 किमी. लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा।

'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व-झाँसी जलसा'

चर्चा में क्यों ?

- 17 नवंबर, 2021 को राज्य सरकार एवं केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में जनपद झाँसी में तीनदिवसीय 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व-झाँसी जलसा'कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झाँसी की रानी के 193वें जन्मदिन को आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम में सैन्य सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, रंगकर्मियों द्वारा जन-सहभागिता को विकसित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे। बुंदेलखंडवासियों के लिये यह अभिनव कार्यक्रम होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनदिवसीय यह कार्यक्रम राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण के भाव को आह्लादित कर रहा है। लोक कथाओं व काव्यों में झाँसी के ओज और तेज को वीर रस के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राई नृत्य की सुंदर प्रस्तुति से लोगों को अभिभूत किया। इससे पूर्व लक्ष्मी व्यायाम मंदिर प्रांगण में सेना के जवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा कार्यक्रम के उपरांत रक्षा मंत्री ने हाथी ग्राउंड पर स्थित रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
- झांसी जलसा कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के झाँसी नोड के पहले प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे।

नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर (APCT) का नोएडा में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह टॉवर डीएनडी एक्सप्रेस वे के ग्रीन बेल्ट में स्थापित किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने स्वदेशी रूप से एक प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टॉवर (एपीसीटी) का डिज़ाइन और विकास किया है।
- यह एपीसीटी अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टॉवर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्त्वों को सोख लेते हैं। इसके बाद टॉवर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है।
- सोखे गए प्रदूषक तत्त्वों को समयानुसार निपटान के लिये एपीसीटी के तल पर हॉपर में एकत्र किया जाता है।
- एपीसीटी से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये बीएचईएल हरिद्वार ऐसे अन्य टॉवरों का निर्माण कर रहा है।
- बीएचईएल के कॉरपोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने इसे डिज़ाइन और विकसित किया है। बीएचईएल, हरिद्वार स्थित प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान एक वर्ष तक एपीसीटी के प्रदर्शन का अध्ययन भी करेगा।

रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झाँसी किला परिसर में आयोजित तीन दिवसीय 'राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व-झाँसी जलसा'कार्यक्रम समापन समारोह में 3425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई तथा ज़िले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, झाँसी का शिलान्यास किया।
- टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों के प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य से 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड'द्वारा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इन परियोजनाओं की लागत क्रमश: 400 करोड़ रुपए और 3013 करोड़ रुपए है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क, झाँसी का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत 11.30 करोड़ रुपए है।
- अटल एकता पार्क भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री दिवगंत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना है। यह पार्क करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस पार्क में एक पुस्तकालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार रामसुतार ने किया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता हैं।
- बुंदेलखंड में बनने वाला उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर भविष्य में भारत के सामर्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई जा रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में विदेशी हुकूमत को हिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जी की शौर्य गाथा को हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ स्मरण करता है।

पीएम द्वारा प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में अर्जुन सहायक परियोजना के साथ-साथ रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना तथा मसगाँव-चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं से प्रदेश के माहेबा, बांदा, हमीरपुर एवं ललितपुर ज़िले के 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी प्राप्त होगा तथा लाखों किसान परिवारों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि होगी।
- मसगाँव-चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, आधुनिक तकनीक पर आधारित विस्तृत परियोजना है, जो सिंचाई में आ रही आधुनिकता को प्रदर्शित करती है। इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल है।
- वहीं अर्जुन सहायक परियोजना की कुल लागत 2655 करोड़ रुपए है तथा इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 44381 हेक्टेयर है। इससे माहेबा, हमीरपुर एवं बांदा ज़िले के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- रतौली बांध परियोजना कुल 54.28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसकी सिंचाई क्षमता 1050 हेक्टेयर है।
- भावनी बांध परियोजना कुल 512.74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसकी सिंचाई क्षमता 3800 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तथा इससे ललितपुर ज़िले को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।

गंगा एक्सप्रेस-वे को मिली पर्यावरण मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने प्रस्तावित 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की निर्माण परियोजना को पर्यावरण मंज़ूरी जारी की।

प्रमुख बिंदु

- पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की 2006 की अधिसूचना के तहत अनुसूची में शामिल परियोजनाओं के निर्माण से पहले पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिसूचना के तहत गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये यूपीईडा (UPEIDA) द्वारा पर्यावरण मंज़ूरी ली गई है।
- इस एक्सप्रेस-वे के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और अब तक लगभग 94 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
- इस एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। यह 6-लेन एक्सप्रेस-वे होगा, जिसे 8-लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह एक्सप्रेस-वे मेरठ-बुलंदशहर रोड (एनएच-334) पर मेरठ के बिजौली गाँव के पास से शुरू होकर प्रयागराज बाइपास (एनएच-19) पर प्रयागराज ज़िले के जुदापुर दांडू गाँव के पास खत्म होगा।
- यह एक्सप्रेस-वे 12 ज़िलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ेगा।
- अनुमान है कि इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान लगभग 12,000 लोगों को अस्थायी रूप से रोज़गार दिया जाएगा, जबकि टोल प्लाजा के निर्माण के बाद लगभग 100 लोगों को स्थायी आधार पर नियोजित किया जाएगा।

यूपी के 35 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले: एडीआर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) द्वारा विधानसभा के 403 मौजूदा विधायकों में से 396 के वित्तीय, आपराधिक और अन्य विवरणों का विश्लेषण करने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसके अनुसार इन विधायकों में से लगभग 35 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 79 प्रतिशत करोड़पति हैं।

प्रमुख बिंदु

- विश्लेषण 2017 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद हुए उपचुनावों में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों पर आधारित है।

नोट :

- एडीआर के अनुसार, यह पाया गया कि विधानसभा के 396 विधायकों में से 140 या 35 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और 106 या 27 फीसदी विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं।
- पार्टीवार भाजपा के 304 विधायकों में से 106, सपा के 49 विधायकों में से 18 और बसपा के 18 में से 2 तथा कॉन्ग्रेस के 1 विधायक पर आपराधिक मामले लंबित हैं।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विधानसभा के 396 विधायकों में से 313 या 79 प्रतिशत करोड़पति हैं।
- भाजपा के पास 77 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक करोड़पति विधायक (304 में से 235) हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 49 (86 प्रतिशत) विधायकों में से 42 करोड़पति है। इसके अलावा बसपा के 16 में से 15 विधायक तथा कॉन्ग्रेस के सात विधायकों में से पाँच करोड़पति हैं।
- विधायकों की औसत संपत्ति 5.85 करोड़ रुपए थी। मुख्य दलों में भाजपा के 304 विधायकों की औसत संपत्ति 5.04 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी के 49 विधायकों की 6.07 करोड़ रुपए, बसपा के 16 विधायकों की 19.27 करोड़ रुपए और कॉन्ग्रेस के 7 विधायकों की औसत संपत्ति 10.06 करोड़ रुपए है।
- मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली कुल 118 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ करोड़पति विधायकों की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद चिलुपार विधानसभा सीट से बसपा के विनयशंकर तिवारी 67 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है।
- 396 विधायकों में से 95 ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 12वीं पास, 290 विधायकों ने खुद को स्नातक या इससे ऊपर घोषित किया है, 4 विधायक अनपढ़ हैं और 5 विधायक डिप्लोमाधारक हैं।
- इसके अलावा 206 विधायकों की उम्र 25 से 50 साल के बीच और 190 विधायकों की उम्र 51 से 80 साल के बीच है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि

चर्चा में क्यों ?

- 24 नवंबर, 2021 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं प्रजनन दर गिरकर 2.7 के मुकाबले 2.4 पर आ गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विगत साढ़े चार वर्ष से अधिक की अवधि में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन तथा कन्या भ्रूणहत्या रोकने के प्रयास सफल हुए हैं। 2015-16 में लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 995 से बढ़कर 2020-21 में 1017 हो गई है।
- इसी प्रकार प्रदेश में खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वाले परिवारों तथा बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले परिवारों में भी बढ़ोतरी हुई है।
- प्रदेश में 2015-16 में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वाले परिवार का प्रतिशत 32.7 था, जो वर्तमान में 49.5 हो गया है। इसी तरह स्वच्छता सुविधाओं में यह प्रतिशत 36.4 से बढ़कर 68.8 हो गया है। यह उज्ज्वला योजना व स्वच्छ भारत मिशन पर प्रभावी तरीके से अमल करने के कारण संभव हो सका है।
- प्रदेश में एनीमिया प्रभावित गर्भवती महिलाओं (15-49 वर्ष) की संख्या में 5.1 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह कमी 1.8 प्रतिशत है।
- प्रदेश में बच्चों के वृद्धि अवरोध के मामलों में 6.6 प्रतिशत की कमी हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 2.9 प्रतिशत है। वही प्रदेश में सामान्य से कम वज़न के बच्चों के मामलों में 7.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 3.7 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार प्रदेश में संस्थागत प्रसव 67.8 प्रतिशत से बढ़कर 83.4 प्रतिशत, परिवार नियोजन के उपाय 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 62.4 प्रतिशत, प्रसवपूर्व जाँच 26.4 प्रतिशत से बढ़कर 42.4 प्रतिशत तथा बच्चों में अतिसार की संक्रमण दर 15 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई है।

नोट :

प्रधानमंत्री ने किया एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 25 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- यह एयरपोर्ट विश्व का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश का 5वाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
- नोएडा एयरपोर्ट को ज्यूरिख एअरपोर्ट इंटरनेशनल (Zurich Airport International AG) द्वारा तैयार किया जा रहा है।
- पहले चरण में नोएडा एयरपोर्ट को 1300 हेक्टेयर ज़मीन पर 10,050 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2024 तक तैयार किया जाएगा। पहला चरण पूरा होने पर नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी।
- नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडन्न की सीओओ किरण जैन ने कहा कि हवाई अड्डे को एक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और सितंबर/अक्टूबर 2024 तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है।
- नोएडा एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर भी होगा जिसमें मल्टीमाडल ट्रांजिट हब, हाउसिंग मेट्रो, हाई स्पीड रेल स्टेशन, टैक्सी, बस सर्विस और प्राइवेट पार्किंग जैसी सुविधाएँ मौजूद होंगी। इन सुविधाओं के चलते सड़क, रेल और मेट्रो के जरिये एयरपोर्ट तक बिना रोक-टोक कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। मेट्रो सेवा के जरिये नोएडा और दिल्ली एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा।
- इस एयरपोर्ट पर स्टेट ऑफ आर्ट MRO (Maintenance, Repair & Overhauling) सर्विस भी उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि इससे ऑपरेटिंग खर्चों को कम रखा जा सकेगा एवं यात्रियों के ट्रांसफर प्रोसेस को शीघ्रता से किया जा सकेगा।
- आसपास की सड़कों, हाईवे जैसे यमुना एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्व फेरिफेरल, ईस्टर्न फेरिफेरल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दूसरे हाईवे को भी एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट को दिल्ली-वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल से भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट की दूरी 21 मिनट में पूरी की जा सकेगी.
- यह एयरपोर्ट स्विंग एयरक्राफ्ट स्टैंड कांसेप्ट के तहत तैयार किया जाएगा जिससे एयरलाइंस उसी contact stand से विमान की पोजीशन को बदले बिना घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकेंगे। इससे एयरक्रॉफ्ट के टर्नअराउंड को जल्दी और आसानी से तथा यात्रियों के ट्रांसफर प्रोसेस को जल्दी से पूरा किया जा सकेगा।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर्यावरण के लिहाज से देश का पहला नेट जीरो एमिसन एअरपोर्ट होगा। पास की जमीन पर पेड़ों को लगाकर फारेस्ट पार्क तैयार किया जाएगा।

निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25

चर्चा में क्यों ?

- 25 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवा प्रदान करना, राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना एवं विकास, निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योगों के निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना, स्थानीय/देश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाज़ार में उपलब्ध अवसरों का चिन्हांकन करना तथा निर्यात संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना है।

नोट :

- निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियाँ, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा पर्यटन, आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस., मेडिकल वेल्यू ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स हैं।
- निर्यात नीति 2020-25 के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य आनुषंगिक क्रिया-कलापों पर होने वाला व्यय बजट में प्रावधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा।
- प्रदेश के प्रत्येक जनपद में क्लस्टर आधारित विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में विकसित की जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि से वित्त पोषित किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25 कृषकों की आय को दोगुना करने तथा कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उन सभी अवयवों को अंगीकृत कर सकेगी, जो उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति -2019 से अनाच्छादित हैं।
- नीति के अनुसार पशु क्रय-विक्रय हेतु ई-हाट पोर्टल विकसित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यातक इकायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष सेवाओं के हायर किये जाने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान नीति में किया गया है।
- प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध अवसरों, प्रदेश में विद्यमान संभावनाओं का उपयोग, युवाओं के लिये रोज़गार सृजन, निर्यात की दिशा में त्वरित वृद्धि, प्रदेश में निर्यात-परक, प्रोत्साहन वातावरण का सृजन इत्यादि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक : उत्तर प्रदेश तीसरा सर्वाधिक गरीब राज्य

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गरीबी के मामले में तृतीय स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश की 37.79 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, जो बिहार एवं झारखंड के बाद देश में सर्वाधिक है।
- उत्तर प्रदेश की 44.47 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, जबकि सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है।
- श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब ज़िला है, जहाँ की 74.38 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। वहीं बहराइच (71.88 प्रतिशत), बलरामपुर (69.45), लखीमपुर खीरी (59.95 प्रतिशत) एवं गोंडा (59.26 प्रतिशत) राज्य के सर्वाधिक गरीब ज़िले हैं।
- लखनऊ राज्य का सबसे कम गरीब ज़िला है, जहाँ के केवल 12.16 प्रतिशत लोग गरीब हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के सबसे कम गरीब ज़िले हैं- (1) लखनऊ (12.16 प्रतिशत), (2) कानपुर नगर (14.34 प्रतिशत), (3) गौतमबुद्ध नगर (17.08 प्रतिशत), (4) गाज़ियाबाद (17.47 प्रतिशत) एवं (5) झाँसी (20.27 प्रतिशत)।
- उत्तर प्रदेश को बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 0.18 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण एमपीआई स्कोर 0.21 एवं शहरी एमपीआई स्कोर 0.085 प्रतिशत है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन शुक्ला पर चलेगा अभियोग

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के एक मामले में भ्रष्टाचार व षडयंत्र के आरोपित लखनऊ पीठ के पूर्व न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के खिलाफ अभियोग चलाने की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह मामला लखनऊ में कानपुर रोड स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़ा है। 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने प्रसाद इंस्टीट्यूट समेत देश के 46 मेडिकल कॉलेजों में मानक पूरे न करने पर नए प्रवेशों पर रोक लगा दी थी।
- जाँच एजेंसी की प्राथमिकी के अनुसार, 24 अगस्त, 2017 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक और याचिका दायर की गई थी। याचिका पर 25 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और उसी दिन संस्था के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसी मामले में न्यायमूर्ति शुक्ला पर भ्रष्टाचार का आरोप है।

नोट :

- सीबीआई ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिये उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी।
- सीबीआई ने न्यायमूर्ति शुक्ला के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद शिक्षा न्यास के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, स्वयं ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडे और सुधीर गिरि को भी FIR में नामजद किया था। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आपराधिक साज़िश) की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश ने फतह किया माउंट पितालसु

चर्चा में क्यों ?

- 27 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट पितालसु (14 हज़ार फीट) को फतह कर भारत का गौरवशाली तिरंगा फहराया।

प्रमुख बिंदु

- माउंट पितालसु पर नीतीश कुमार सिंह ने अपनी चढ़ाई 24 नवंबर को शुरू की थी। उन्होंने इस मिशन को दिल्ली की संस्था सहयोग केयर फॉर यू के साथ मिलकर पूरा किया।
- इसके साथ ही नीतीश ने माउंट पितालसु से बाल यौन शोषण, मतदाता जागरूकता व स्वच्छ गोरखपुर का संदेश दिया।
- हाल ही में पर्वतारोही नीतीश को गोरखपुर के उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु गोरखपुर का 'यूथ इलेक्टर आइकन ऑफ गोरखपुर' भी बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के राजेंद्र नगर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह ने इस वर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी को भी फतह किया है, जिनमें पहली अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो और दूसरी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रूस हैं।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान

चर्चा में क्यों ?

- 29 नवंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान के शताब्दी समारोह में 'शताब्दी स्तंभ'का अनावरण तथा डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस शताब्दी स्मारिका में प्राणि उद्यान की 100 वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है।
- इसके साथ ही उन्होंने 'चित्रों में चिड़ियाघर'नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया तथा वन्य जीव संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रशासकों एवं पूर्व निदेशकों को भी सम्मानित किया।
- इस अवसर पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वन्य जीव एवं पर्यावरण पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- मुख्यमंत्री ने प्राणि उद्यान के जीव-जंतुओं के अंगीकर्ताओं को भी सम्मानित किया। साथ ही बच्चों द्वारा सुझाए गए नाम के आधार पर 6 बाघों का नामकरण किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में 2 प्राणि उद्यान ही बन पाए थे, जबकि विगत 5 वर्षों में एक प्राणि उद्यान गोरखपुर में स्थापित किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि यह प्राणि उद्यान लखनऊ के मध्य में बसा है, जो प्रदेश के लोगों के लिये एक आकर्षण का केंद्र है। साथ ही, लखनऊ नगरवासियों के लिये यहाँ के पेड़-पौधो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्लांट के रूप में हैं। यहाँ पर दृष्टिबाधित लोगों के लिये एक गैलरी की स्थापना भी की गई है।

नोट :